पत्रिका

पत्रिका

ग्वालियर .शुक्रवार . 18.03.2016

पोस्टल रजि. नं. म.प्र. /ग्वालियर/583/2013-15/2012

बिना जरूरत के लाए गए तीन अनुपूरक बजट पर कैग ने उठाए सवाल

वित्तीय प्रबंधन में सरकार फेल

भोपाल. राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल है। वह पिछले साल का मूल बजट ही खर्च नहीं कर पाई, इसके बावजूद सरकार तीन-तीन अनुपूरक बजट लेकर आ गई, जबकि इनकी जरूरत ही नहीं थी। यह खुलासा नियंत्रण महालेखा परीक्षक(कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग के मुताबिक सरकार के सभी अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए हैं।

35 हजार करोड़ बचे बजट से

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट में 1,48,505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें से सिर्फ 1,13,052 करोड़ ही खर्च हुए। सरकार को सभी मदों में 35 हजार 453 करोड़ की बचत हुई थी। बावजूद सरकार 19 हजार 504 करोड़ के यह तीन अनुपूरक बजट लेकर आई जो गैरजरूरी थे।

सरकार बीते कई सालों से लगातार अनुपूरक बजट ला रही है। इस बार सर्वाधिक चार अनुपूरक बजट पेश किए गए। इससे पहले तीन-तीन और दो-दो अनुपूरक बजट पेश हुए। सरकार का बजट प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण राजकोषीय घाटे में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 1470 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया कि विभागों द्वारा खर्च नहीं की गई रकम में से सिर्फ 49.64 प्रतिशत ही सरेंडर की गई। इनमें 117 मामले ऐसे है जिसके 16148 करोड़ रुपए की बचत वित्त वर्ष के अंतिम दिन समर्पित की गई, जिससे इसके अन्य विकास के कामों में उपयोग की गुंजाइश नहीं बची। पढ़ें वित्तीय.. @ पेज 11

यहां भी चपत

कैग रिपोर्ट : 2,33,068 प्रकरणों में पकड़ी

प्रदेश में जमीनों के खेल में 416.15 करोड़ रुपए की चपत सरकारी खजाने को अफसरशाही ने लगा दी। इसमें सीधे तौर पर 163.94 करोड़ रुपए तो ऐसे रहे जो टैक्स लगाया जाना था, किंतु बाबूगिरी के गठजोड़ से इसे लगाया ही नहीं गया। इसके अलावा 180.72 करोड़ रुपए की गडबड़ भी पकड़ में आई है। 122 निकायों में 2,33,068 प्रकरण ऐसे मिले, जिनमें जमीनों के राजस्व में गड़बड़ियां मिलीं।

लम्बित मामलों से 34 करोड़ का नुकसान

30 जून 2015 तक विभिन्न विभागों में 3134 प्रकरण ऐसे लम्बित थे, जिनमें शासन को 34.37 करोड़ का नुकसान हुआ है। वर्ष 2014-15 में 446.28 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

वाहनों से टैक्स में 20 करोड़ रुपए का झटका

प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों से टैक्स वसूली में सरकार को 20.02 करोड़ का नुकसान हुआ। 356.51 करोड़ की राजस्व वसूली की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है। 3.30 लाख से ज्यादा प्रकरणों में टैक्स वसूली व निर्धारण की गड़बड़ी पाई है। इसमें लोकसेवा वाहनों पर टैक्स वसूली में गड़बड़ी से 11.68 करोड़, माल वाहनों पर टैक्स वसूली में गलत निर्धारण से 3.44 करोड़ और कैब पर कम टैक्स से 2.79 करोड़ की चपत लगी है।

वित्तीय..

टैक्स में 1486 करोड़ की चपत: प्रदेश सरकार को टैक्स में 1486.50 करोड़ का घाटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्पादन शुल्क, वाणिज्य कर, वाहन टैक्स, भू-राजस्व, खनन, वन और बिजली में 1486.50 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना कम पाया गया है। इसमें बकाया वसूली नहीं होने से लेकर टैक्स का गलत निर्धारण और गड़बड़ी तक शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि कैग ने इस राशि का नुकसान सरकार के विभागों को बताया, तो उन्होंने 411.49 करोड़ की कमी को स्वीकार किया। इसके तहत 654 प्रकरणों में 4.85 करोड़ की वसूली भी की।